COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

SIXTY-FIRST REPORT

SHRI R. P. YADAV (Madhepura) : I present the Sixty-first Report of the Committee on Public Undertakings on Action Taken by Government on the recommendations contained in their Fifty-first Report on India Tourism Development Corporation Ltd.

DELHI SALES TAX BILL

(i) REPORT OF SELECT COMMITTEE

SHRI S. M. SIDDAYYA (Chamarajnagar) : I present the Report of the Select Committee on the Bill to consolidate and amend the law relating to the levy of tax on sale of goods in the Union territory of Delhi.

(ii) EVIDENCE BEFORE SELECT COMMITTEE

SHRI S. M. SIDDAYYA . I lay on the Table the record of evidence tendered before the Select Committee on the Bill to consolidate and amend the law relating to the levy of tax on sale of goods in the Union Territory of Delhi.

12.05 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH) : Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing the 21st April, 1975, will consist of :—

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's order Paper.

2. Discussion and voting on the Demands for Grants relating to the Ministries of :

   (1) Home Affairs

   (2) Supply and Rehabilitation.

I may also inform the House that it is proposed to take up on 23rd April, 1975 for consideration and passing two constitution Amendment Bills—one relating to Sikkim and the other relating to Arunachal Pradesh.

MR. SPEAKER : I have been requesting the Members that when they make submissions, they should be brief and they should not take more than two minutes and they should not speak on more than one point. Already there are 20 members who want to speak. I have, therefore, to reduce the time to accommodate such a big list of names.

श्री राम चन्द्र विकल (बागपत) : किसानों को जो बोनस देने का सरकार ने फैसला किया है मैं समझता हूं कि इस में काफी कुरप्शन होगा और इसको किसान पसन्द नहीं कर रहे हैं मैं चाहता हूं कि सरकार बोनस के बजाय मूल्यों म वृद्धि करे और मूल्यों में वृद्धि करना ज्यादा अच्छा भी होगा । मैं चाहता हूं कि कृषि मन्त्री इस पर पुन: विचार करे और जो मूल्य है उसको बढ़ा कर 125 रुपया कम से कम कर दें ।

SHRI VASANT SATHE (Akola) : I would like in the next week's business discussion on the important issue relating to the policy of allowing private sector or private persons to make investments in public sector undertakings. The Government should come out with a clear policy statement on this because in the Bharat Heavy Electricals, Hardwar recently a memorandum was submitted by the workers of the factory opposing this and it is learnt that the Prime Minister has given them an assurance that private investment in public sector will not be permitted. I would, therefore, like a clarification be made on this matter and this important matter should be discussed next week.

SHRI DHAMANKAR (Bhiwandi) : I want to raise the matter of the Zuari Agro-Chemicals, Goa. This factory in Goa has not taken proper steps to treat the ammonia effluents and is thereby causing havoc and is polluting the whole area as also water. As a result vast areas of rice fields have been rendered barren. Even the labour have refused to load and unload the raw material and finished products for the factory. The Goa Government also have demanded the closure of the factory. I request that this matter should be discussed by the House.

श्री राजाभाऊ खापर्डी (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मनुष्य के लिए भोजन, वस्त्र और पीने का पानी ये तीन बहुत ही आवश्यक वस्तुएं हैं और पीने का पानी तो इन में सब से ज्यादा जरूरी है। बिना पानी पिए गर्मियों के दिनों में तो लोगों का जिन्दा रहना ही मुश्किल है। मैं आप के माध्यम से बिहार के विभिन्न जिलों में पीने के पानी का जो अकाल है उसकी ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। पटना शहर बिहार की राजधानी है। वहां पटना शहर के बाकीपुर इलाके में और पटना सिटी में पानी नहीं मिल रहा है। बांकीपुर के इलाके के पुनाईचक और लालजी टोला में और पटना सिटी के पच्छमी दरवाजे में पानी का अकाल है। उसी तरह से छपरा में होली के बाद से पीने का पानी मिलना मुश्किल हो गया है। मुंगेर में एक पखवाड़े से पानी नहीं मिल रहा है और लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। इसी तरह से खगरिया शहर, संथाल परगना के बरहडवा और गोडा के महागामा, मेहरामा, बेगुसराय शहर, रोहतास जिले के चैनपुर सहसराम, भोजपुर के बकसर आदि स्थानों में पानी नहीं मिल रहा है। ये सब नाम बिहार के अखबारों में आ चुके हैं और उन अखबारों में रोज आपको इसके सम्बन्ध में खबरें पढ़ने को मिल जाएंगी। पूरे राज्य में पेय जल की कमी हो गई है, पानी का अकाल पड़ गया है। लोगों को दफ्तरों में जाने में इस कारण से दिक्कत हो रही है। पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, नहाने की बात तो लोग भूलते ही जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में यहां बहस करे और बताए कि पानी की समस्या का समाधान वह कैसे निकालना चाहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप बिहार सरकार को इस संकट को हल करने में विशेष अनुदान दें और उसकी मदद करें ताकि पूरे बिहार की पेय जल की समस्या का, इस संकट का हल निकाला जा सके। बिहार में हर तरह का संकट है लेकिन पानी का संकट सब से बड़ा संकट है। इसकी ओर मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में एक बयान देगी और वहां की सरकार की मदद करेगी।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपने नोटिस में प्वाइंट कोई नहीं लिखा है। वह आपको लिखना चाहिये था। आज तो मैंने आपको आज्ञा दे दी है लेकिन आगे से नहीं दे सकूंगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरैना) अनेकों वर्षों से शेड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिशनर की रिपोर्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई है। उसमें अनेक बातें उठाई गई हैं जिन पर चर्चा करना आवश्यक है। देश के विभिन्न भागों में हरिजनों और आदिवासियों पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं न तो उनको रोका जा रहा है और न ही इस समस्या का कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है। आप राज्य सरकारों को पैसा दे देते हैं, उनको सहायता दे देते हैं, अनुदान दे देते हैं लेकिन उनका भी वे उपयोग नहीं कर पाती हैं। पिछली बार हरियाणा में काफी पैसा लैप्स हो गया। मैं चाहता हूं कि इस रिपोर्ट पर चर्चा का हमें अगले सप्ताह मौका दिया जाए।

शैड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में जो एमेंडमेंट बिल है वह अनेक वर्षों से पड़ा हुआ है। एक कमेटी भी बनी थी जिसने सारे देश में घूम कर अपनी रिपोर्ट दी थी। बिल तैयार किया गया था उसके बाद लेकिन उस पर आप चर्चा नहीं करवा रहे हैं। क्यों आप उसको यहां नहीं ला रहे? कब तक आपका उसको यहां लाने का विचार है?

जो कमिशन की रिपोर्ट है उस पर चर्चा करने के लिए बहुत से माननीय सदस्य उत्सुक हैं। उनकी स्थिति दयनीय है। उन पर अत्याचारों का ताता लगा हुआ है। इस समस्या का क्या हल निकल सकता है, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य क्या सुझाव देना चाहते हैं, इसको जानने के लिए आप हमें

अगले हफ्ते उस पर चर्चा करने का अवसर दें, यही मेरी आप से प्रार्थना है।

MR. SPEAKER : Mr. Samar Guha, you have not mentioned on what point ; you have not mentioned about anything ; you must write.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : I always obey your order that I should raise only one subject.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : You can imagine on what topic the will speak...

MR. SPEAKER : I am happy on the observation, but you should write the subject.

श्री सरजू पांडे (गाजीपुर) : एक सप्ताह हुआ मैंने भी लिख कर आपको दिया था। पता नही मेरे नोटिस क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : बिजनेस आज अनाउंस हुआ है और आप एक हफ्ता पहले लिखकर दे चुके है।

श्री सरजू पांडे : पता नही वह कहां खो गया है। बताइये कि क्या यह हमारे साथ ज्यादती नही है।

SHRI SAMAR GUHA : The Minister for External Affairs, in the course of his reply to the debate expressed his concern about Khan Abdul Ghaffar Khan, the Frontier Gandhi.

Sir, I want that the Minister of External Affairs should come out with a statement next week on how a concern was expressed by him in the course of the debate on the demands of External Affairs about Shri Khan Abdul Ghaffar Khan and in what shape he would express that concern I want to know whether our Foreign Missions will be instructed to mobilise international opinion in favour of Shri Khan Abdul Ghaffar Khan's Security. Also I want to know since this is a sacred matter and for six or seven years, he had been in Afghanistan and then he came to Pakistan and since he is not now being allowed to go to Afghanistan and is being kept interned although there is no charge of any conspiracy against him from Government whether the issue of genocide and repression would be raised in the proper forum like the UNESCO and others. There is a large number of exodus of refugees from Baluchistan and Pakistan and they have entered into Afghanistan, I want to know also from Government whether they will come out with a statement for giving them assistance.

I want further to add that they were compatriots and comrades-in-arms to the last moment in the main current of our freedom struggle and so we should not forget that and we should not frustrate them. At least we should feel in our conscience that it is our secured trust to uphold their cause.

श्री भोगेन्द्र झा (ऊधनगर) : अध्यक्ष महोदय, अब दक्षिण वीतनाम की आजादी के पूर्ण होने का दिन करीब करीब नजदीक आ गया है। वहां का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा, नानपेन्ह शहर और बन्दरगा आदि आजाद हो गये हैं, पर अभी तक हमारी सरकार ने न उन को मान्यता दी है और न राजनीतिक सम्बन्ध कायम किया है। मैं चाहता हूं कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर मंत्री महोदय वक्तव्य दें। वहां पर जो नरसंहार अमरीकी बमबारी ने किया है, उस के कारण वहां के नागरिको को अनेक प्रकार की सहायता की आवश्यकता है और यह एक ऐसा मौका है जबकि एक मित्र की तरह, हम उनको डाक्टर और दवाइयों को सप्लाई करें और दूसरे मामलो मे भी उनकी तुरंत सहायता करें। यह खासकर इसलिए भी जरूरी है कि जिस अमरीकी साम्राज्यवादी का हिन्द महासागर में हमारे ऊपर घेरा पड़ रहा है और वहां से वह जो हथियार भेज रहा है, उस का मुकाबला करके उन्होंने उस को परास्त किया है। इस तरह से वे एक तरह से हमारी लड़ाई भी लड़ रहे है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह इस विषय को रखा जाए और इस पर विचार करने का समय निश्चित करें। यह न हो कि सब मामला जब खत्म हो जाए, तब सरकार एक पोस्ट-मार्टम की तरह आए।

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad) : Mr. Speaker, Sir, as the House knows, Gujarat goes to the polls for the new Vidhan Sabha in early June. To

[Shri P. G. Mavalankar]

ensure free and fair elections, I demand that the Administration in Gujarat must function in a scrupolosly impartial manner and devote all their time and energy to the question of giving relief to the scarcity h t people.

I also invite the attention to the fact, especially because the Prime Minister herself is reported to be going next week to some parts of Gujarat, particularly, the districts of Jamnagar, Rajkot etc., that the State Government had approved the plans of 494 Check Dams during the year 1974-75 in five districts of Saurashtra. These districts are Rajkot, Bhavnagar, Jamnagar, Junagadh and Amreli. The amount sanctioned was Rs. 2.5 crores. All these schemes are shelved reportedly due to shortage of funds. Therefore, I would like the Administration to get some funds so that they can devote themselves entirely to the work of drought relief and leave the politics to the politicians and the candidates. I say this because the Governor and his two Advisers, particularly, Shri H. C. Sarin, are going about and making public and political statements which have direct or indirect effect on the poll. I would, therefore, like the Governor and the Advisers to be free from this. May I refer, in conclusion to the news that the Prime Minister is also going there next week.

I would like to know wthether she has decided about this just now or it was decided long time back. The Prime Minister and other Central Ministers should also refrain from under taking any official tours during the ensuing weeks. I want the Home Minister to make a statment assuring the conduct of free and fair elections in my home-State.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : Sir, I will take only little time. Four thousand workers have been laid off by Hindustan Motors at Uttarpara in West Bengal. At the same time not less than 50 industrial units have shifted their offices from West Bengal causing serious unemployment problem. I would request the hon. Industries Minister to make a statement on the Floor of the House to give us a clear picture as to what is there in stores for us in the future.

Secondly, there has been a serious case of repression and atrocities on a Bowri [illegible] woman in Birbhum district of West Bengal. I would like the Home Minister to make a statement in this connection.

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, कुछ विस्थापित लोगों की समस्याओं के बारे में मैं मंत्री महोदय से अगले सप्ताह में वक्तव्य चाहता हूं। यह जो पौंग डेम, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, वहां के कुछ विस्थापित लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे। वहां पर एक लाख 35 हजार लोग विस्थापित हो गये हैं।

MR. SPEAKER : That is not the poin which you wanted to raise.

श्री मधु लिमये : मैं विस्थापितों के बारे में कह रहा हूं। कई तरह के विस्थापित हैं। दो प्वाइंट्स कहने की बजाए, मैं एक ही में कह रहा हूं। (व्यवधान) उन को ठीक ढंग से नहीं बसाया जा रहा है और उस के बारे में मैंने लिखा है लेकिन नोटिस में मैंने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि दिल्ली केन्द्र शासित इलाके में कई गावों में दिल्ली डेवलपमेंट आथेरिटी इस ढंग से काम कर रही है जिस से बहुत से लोग विस्थापित होते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह दिल्ली डेवलपमेंट आथेरिटी का सर्कूलर है और इस में जगमोहन जी कहते हैं :

> "As Secretary is aware our policy is not to acquire old built up areas or .... which had been mentioned as such in the revenue records before the date of preliminary notification."

इसके बावजूद, अध्यक्ष महोदय, पोसगीपुर आदि इलाको में बहुत सारी ऐसी जमीन है जहां पर बहुत से बिल्ट-अप एरियाज है और उन को लिया जा रहा है और वहां पर लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। तो मैं केन्द्रिय गृह मंत्री जी से इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य चाहता हूं कि आखिरकार दिल्ली डेवलपमेंट आथेरिटी के जो नियम हैं, जो नीति है, उनके ऊपर अमल होगा या जो बिल्ट-अप एरियाज में सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं, उनको विस्था-

दिया जाएगा। इसके बारे में मैं मंत्री जी का वक्तव्य चाहता हूं।

SHRI NOORUL HUDA (Cachar): Sir, there are about 50,000 Manipuris Bishnupia linguistic minority in the district of Cachar in Assam. In spite of the repeated recommendation by the linguistic Commissioner the Government of Assam has not yet been able to impart primary education in local primary schools in the district of Cachar which has been agitating the minds of Manipuris Bishnupia. I would like the Home Minister to persuade the State Government of Assam to impart primary education in the language of Bishnupia manipuri in the district of Cachar.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Mr. Speaker, Sir, with your permission I would like to raise a very important matter. I do not want any confrontation of Central Government employees with the Government. Sir, you are aware that five instalments of dearness allowance are legitimately due to the Central Government employees on the basis of the recommendation of the Pay Commission and which has been accepted by Government. This is due from 1st October 1974. Sir, a soleman assurance was given by the Minister, Shri Jagjivan Ram, on behalf of the Government, that from 15th March, negotiations will start as to how these five instalments of dearness allowance are to be paid and whether a wage revision was necessary. Sir, when the representatives of the Central Government employees met the Finance Secretary and other officials recently, the Finance Secretary explained to us the various economic difficulties faced by the Government. He pleaded with us that the representatives of the Central Government employees should cooperate with the Govenment. Sir, whether it is cooperation or sacrifice, I do not know. Why should only the 28 lakh Central Government employees be held responsible for the reaction of these conditions? The economic conditions have gone bad because of the high prices and inflation. The representatives of the Central Government employees have made it abundantly clear to the hon. Finance Minister and the Finance Secretary that under no circumstances, they should be made to forego the five instalments of dearness allowance. Another meeting is going to be held on the 21st April 1975. My information is that the Finance Minister is going abroad. Therefore, suitable instructions should be issued to the Finance Secretary not to bring pressure on the Central Government employees to sacrifice for nothing. When the employees in the public sector undertakings get a fair deal from the Government, why should only the Central Government employees sacrifice and not get the five instalments of dearness allowance? On behalf of all those employees and organisations, I would like to make it clear to the hon. Finance Minister and to the Government that the Central Government employees are prepared to have negotiations for better wages according to the recommendations of the Pay Commission, if these five instalments of dearness allowance are paid to them. We are prepared to consider other aspects of the case, if the Government is also prepared to consider our demand for cheap grain shops for supply of essential commodities at reasonable prices. But, these five instalments of dearness allowance should be paid first to the Central Government employees. I would request that a statement should be made by the hon. Finance Mmister. The Central Government employees are patiently waiting. This inflationary situation is the creation of the Government and the Central Government employees should not be held responsible.

श्री राम रतन शर्मा (बांदा): मैं एक गम्भीर प्रश्न उठाना चाहता हूं और संसद कार्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको वह अगले सप्ताह की कार्रवाई में शामिल करें। साथ ही वह मंत्री जी से कहें कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के विद्रोहियों को सरकार दबा नहीं सकी है। अभी कुछ दिन पहले धर्मवीर सिंह आर्य जो वहां पर इंस्पैक्टर जनरल हो कर गए थे, उनकी वर्दनाक हत्या की गई थी। उसके साथ ही और भी बहुतों को वहां मौत के घाट उतारा गया है। अब पैट्रियाट में एक समाचार छपा है जिसको मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:

> "A secret hospital complex is reported to have been set up deep in the jungles of Mizoram by christian missionaries for Mizo, Naga and Manipur underground. Besides treating the hostiles injured in

[श्री राम रतन शर्मा]

the clashes with the Armed Forces, the secret hospital is also understood to be functioning as the medical headquarters of hostiles in the three areas. The Government of India came to know of it very recently and conducted investigations, it is learnt. Sometime ago, a group of armed Mizo rebels is reported to have sneaked back into Mizoram from Burma."

मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य वह अगले सप्ताह देने की कृपा करे।

श्री शरद यादव (जबलपूर) : मैं आज एक ऐसा मामला उठाना चाहता हूं जोकि लाइसेंस देने से सम्बन्धित है। यह एक बहुत गम्भीर मामला है और आयात लाइसेंसो से सम्बन्ध रखता है। इदौर की बोगस आयुर्वेदिक फर्मों को आयात लाइसेंस दिए गए हैं। इदौर की 374 फर्मों मे से लगभग तीन सौ फर्में बोगस पाई गई है। एक करोड नब्बे लाख रुपये के लाइसेंस उनको दिए गए और जिनको दिए गए उन्होने कच्चे माल को काले बाजार मे बेचा और कीमती विदेशी मुद्रा जो हमारी थी वह बरबाद हुई। काले बाजार मे आठ दस करोड मे इनको बेचा गया। इस मामले की जांच भी हुई थी। श्री पाहुजा डी आई जी थे और जांच कमेटी में बैठे थे जाच रिपोर्ट के आधार पर जो छोटे अफसर थे, ड्रग इस्पैक्टर वगैरह थे उनको तो सजा दे दी गई लेकिन बडे अफसरो के खिलाफ कोई कार्रवाई नही हुई। यहां की एक मंत्री विमला वर्मा, इनकी पार्टी के श्री गारगी शकर मिश्र और श्री नरेन्द्र साल्वे आदि इस पूरे मामले मे शेरीक है। इन लोगों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नही हुई है। जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आठ दस करोड का यह मामला है। यह मामला एक दो साल से नहीं चल रहा है, 1971-72 के बीच मे तीन सौ बोगस फर्मों को लाइसेंस दिए गए और उसके बाद जांच पड़ताल हुई। फ्रेंकलिन नाम का व्यक्ति जो भोपाल में रहता है और जान बचाने के लिए भाग कर रहा है उसकी बाकी कनैहया लाल मेहता जो कांग्रेस पार्टी के मन्त्री है, सचिव है उनकी लड़की से हुई है और उन्होंने पांच करोड़ तक के लाइसेंस लिए है सरकार से। गोहरा ग्रुप इसमें शामिल है। दो चार साल से इस तरह के मामले चल रहे हैं। तेरह घर इस तरह के हैं जिन के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने आयात लाइसेंस लिए और बोगस नामों से लिए। जो फर्में थी उन मे से एक भी फर्म इदौर नगर मे पाई नहीं गई है जो बोगस न हो। क्या यह केन्द्र का मामला नही है। आयात लाइसेंस या आयात की अनुमति कौन देता है? यह मामला मध्य प्रदेश के तमाम अखबारो, नव भारत, नई दुनिया से ले कर जितने भी दूसरे अखबार है उन मे छप चुका है। तमाम अखबार इस से रंगे हुए है विधान सभा में भी यह मामला उठ चुका है। वाणिज्य मंत्री का यह मामला है। वह इस मे पैसा खा रहे हैं, कांग्रेस फंड के लिए पैसा ले रहे है, चुनाव की होली खेलने के लिए इसमे से काफी पैसा उनको काले धन के रूप में मिला है, गारगी शकर मिश्र पूरी तरह से इस मामले में इनवाल्ड है। वह कोई सफाई नही दे सके है। मैं जिम्मेदारी के साथ यह मामला उठा रहा हू। गारगी शकर मिश्र, नरेंद्र साल्वे, ये दो व्यक्ति इस हाउस के सदस्य है, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो मध्य प्रदेश के अन्दर लाखो रुपये खाने का मामला चला रहे हैं, रुपया खाया जा रहा है। मैं जानना चाहता हू कि क्या मंत्री महोदय इतने बडे बोगस मामले की, इतने बडे भ्रष्टाचार की जांच करने की बात सोच रहे हैं? पहुजा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके फलस्वरुप छोटे अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई तो हुई लेकिन बडे अफसरों के खिलाफ क्यों नही हो रही है? ये लोग जो पैसा खा पी रहे हैं उनको खाने पीने की क्यों छूट दी गई है?

अध्यक्ष महोदय : जब भी किसी मेम्बर के खिलाफ आपको कोई एलीगेशन करना हो तो स्पीकर को पहले नोटिस देना पड़ता है। किसी

का नाम लेकर एलीगेशन लगाना हो तो रूल में यह है कि स्पीकर को इनफार्म करना पड़ता है; रूल इसके बारे में क्लीयर है।

श्री मधु लिमये : रूल में यह है वे कि सफाई दे सकते हैं।

SHRI K. RAGHU RAMAIAH : I have a submission to make. He has already named the persons. This will get wide publicity. No notice has been given to the hon. members to contradict him. It is a very anomalous situation....

MR. SPEAKER : I think he was not aware of the rule.

SHRI MADHU LIMAYE : Let them give personal explanations.

SHRI K. RAGHU RAMAIAH : Ignorance of the rule is no justification. I submit for your consideration whether the matter should not be held over without publicity until the hon. members have had notice and are able to contradict it because otherwise it will do a lot of damage. They should be protected in this matter.

MR. SPEAKER : I am very sorry this rule was not observed by the member. Perhaps he is new.

श्री चंद्रिका प्रसाद (बलिया): माननीय सदस्य ने विमला वर्मा जो मध्य प्रदेश की हैं जो इस हाउस में नहीं है, उनका नाम लिया है। मैं चाहता हूं कि उनके इस रिमार्क को एक्सपन्ज किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि वह नए हैं, शायद उनको रूल का पता नहीं है, किस का भी नाम लेना हो तो स्पीकर को नाम भेजना पड़ता है।

श्री शरद यादव : यह मामला वहां विधान सभा में आ चुका है।

MR. SPEAKER : I am sorry the rule was not observed by the member. The names should have been given to the speaker. This applies to men in public also.

श्री भारत सिंह चौहान (धार): अध्यक्ष महोदय मैं कृषि मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और चाहता हूं कि वे वक्तव्य दें कि 8 साल पहले जो गो-रक्षा सम्बन्धी एक बहुत बड़ी मांग हुई थी और एक केन्द्रीय समिति स्थापित की गई थी शासन द्वारा, उस सम्बन्ध में कोई भी रिपोर्ट सदन में पेश नहीं हुई है। समय समय पर लोक-सभा में मंत्रियों ने भी आश्वासन दिये थे कि हम शीघ्र ही इसकी रिपोर्ट मंगा कर सदन में पेश करेंगे। समय समय पर ऐसे भी आश्वासन दिये गये थे कि आर्टिकल 48 के अधीन हम राज्यों को लिखेंगे और वह लिखा भी गया, लेकिन उसका कोई भी पालन नहीं हुआ। आज परिस्थिति यह बनती जा रही है कि चारों तरफ से एक अशांति का वातावरण बनता जा रहा है। मंत्रियों द्वारा लोक-सभा में आश्वासन देने के उपरान्त भी उसका कोई पालन नहीं हो रहा है। हर मंच से चाहे साधु समाज का मंच हो या धार्मिक मंच हो, इस सम्बन्ध में एक बहुत बड़ा तीव्र आन्दोलन पुनः आरम्भ होने की संभावना है।

मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि जिस तरह से आश्वासन दिये गये हैं और उनको पूरा करने के लिये समय समय पर स्टेटमेंट दिये गये हैं, वह शीघ्र ही अगर पूरे न किये जायगे तो देश में एक भारी तूफान आयेगा, यह आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। क्योंकि इस वक्त में हर मन्च से इस बात के पुनः आन्दोलन की संभावना बढ़ती जा रही है।

यही नहीं, मैं आपको इस गोरक्षा के सम्बन्ध में कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि गोबर और उसकी शक्ति के बारे में किस तरह से आज विदेशों में भी खोज की जा रही है और वह खोज सामने आई है। यहां पर मैं आपको एक रूस की खोज के बारे में पढ़कर सुनाता हूं :—

"रूस में खोज के विशेषज्ञ श्री जोरेलेसाम ने सिद्ध किया है कि गोवन्श के गोबर का

[श्री बालचन्द्र सिंह चौहान]

जहां लेपन होगा वहां पर हाईड्रोजन बम तथा एटम बम आदि का प्रभाव नहीं होगा। अभी भी रूस में गोबरगैस पर खोज चल रही है। इससे गैस प्लान्ट तैयार कर अरबों रुपये की शक्ति तयार की जा सकती है। अब तो गैस से मोटर चलाने का भी प्रदर्शन दिल्ली में हुआ है। इन्हीं कारणों से पुराणों में गोवंश और गोबर में लक्ष्मी और मूत्र में गंगा का निवास बताया था। रासायनिक खाद बारबार डालने से भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। इसके प्रयोग में पानी अधिक चाहिये। किन्तु आज सिंचाई के साधन पर्याप्त नहीं हैं। रासायनिक खाद के आयात तथा निर्माण में विदेश मुद्रा व्यय होगी।"

तो दरअसल अब तक इस बारे में ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं कृषि मंत्री से चाहता हूं कि जो आश्वासन दिये गये हैं उनको शीघ्रता से पूरा किया जाये।

आजादी के पूर्व भी गौ-माता के नाम पर ये आश्वासन दिये गये थे कि आजादी आने के बाद गोवध बन्द कर देंगे। लेकिन आज तक 27 साल हो गये, वह पूरा नहीं किया गया है।

ये जो लोग सामने बैठे हुए हैं, इनकी भी आत्मा कहती है लेकिन ये लोग हिम्मत के साथ इस बात को नहीं कहते हैं। दिल में चाहते हैं लेकिन आगे नहीं आते। इनकी आत्मा मर चुकी है, यह ध्यान रखिये।

SHRI SEZHIYAN (Kumbhakonam) : I wrote you a letter regarding the use of names and nomenclatures of ministries and Departments, Hindi equivalents written in Roman script. Strictly that does not come within the purview of the business for the next week but I had been told by your office that I might raise the matter now. I remember that in the second session of the Fifth Lok Sabha in 1972 this new procedure was being introduced and at that time there was objection from many Members of the House. Later on it was decided that in all the correspondence and papers given to this House they would write the names etc. in English followed by Hindi equivalent written in Devanagri scripat. This was the accepted position and I thought it would be followed. Now and then I find that it is being violated. Many papers laid on the Table, many reports, etc. were in clear violation. Last year I raised it and this year also on 9th January 1975 I wrote a letter to the Minister. I appreciate the efforts of the Minister of Parliamentary Affairs; he issued a circular in February informing the various Ministries of the accepted position and stated on the floor of the House also. In my letter I made it clear :

> "I am writing this letter in advance so that in case the decision of the House is not taken somewhat more seriously by the Government and the House and if any report or paper is presented to the House contravening the announced decision I shall insist on the withdrawal of the same."

After that letter was written the Department of Parliamentary Affairs issued a circular inviting their attention to my letter and they have specifically stated on February 13, 1975 in their circular :—

> "The Minister of Parliamentary Affairs has announced on the floor of the House that the designation of the Ministries and the names of the Ministries and department etc. should be written in English followed by Hindi equivalents in Devanagari script for all parliamentary business."

That had been made clear. But even after the issue of the letter many departments are continuing to issue their reports and are placing papers on the Table of the House using Hindi equivalent in Roman script. I can point out so many examples : the report of the Ministry of Agriculture and Irrigation, Department of Irrigation; the report for the year 1974-75, Ministry of Agriculture and Irrigation, Department of Agriculture, the 1974-75 report of the Ministry of Defence. There are so many. We are now discussing the Demands of the Ministry

of Defence. Even that report says : Government of India—Bharat Sarkar ; Ministry of Defence—Raksha Mantralaya.

A decision is taken; it is accepted; it is announced in the House; circulars are issued again and again to all the departments and as late as February this year, they had issued a circular asking for implementing a decision taken four years ago. I want the position to be made clear. If they want to use this method, let them use it but at least announce the decision and then do so ; we must know where we stand. Therefore, I seeks your guidance. In this case the Minister of Parliamentary Affairs is helpless. He issues a circular but that is flouted by many departments. In the case of many papers laid on the Table this decision had been completely flouted. Therefore, I seek your permission and your ruling when a decision is repeatedly flouted by various departments of the Ministries of the Government.

SHRI B. N. REDDY (Miryalguda) : Due to continuous fall in the price of cotton lakhs of cotton growers had been badly hit and this will hit cotton production. I request the Government to announce a fair minimum price for the producer and direct the cotton corporation to enter the market in a big way. An agitation for the payment of minimum fair price for cotton has been going on in Andhra Pradesh for months and months. Thousands of kisans who have made huge investments for increasing production are coming to the collectorate and staging a dharna. Recently a big hartal took place in Guntur and Mr. Raghu Ramaiah knows it. A representation was given to him on behalf of cotton growers. I do not know why the Government is keeping mum on such an important matter. Perhaps Government is not taking any steps because they want the traders to buy the cotton at lower prices and make profits later. This is the method of the Government. After the cotton growers have exhausted their stocks of cotton, Government will start making purchase according to their own rates. By this policy Government is helping the monopoly trade interests. So, in the interest of cotton production and earning of valuable foreign exhange, Government should announce the minimum fair price for cotton. Government has not acted so far. I request the Government to allow a discussion on this matter.

About 10 people have been killed in Guntur district in Vinukonda taluk on the 16th of this month in the name of controlling a clash. Even if the clash had taken place, 10 people would not have died. I request the minister to make a statement on this very grave mishandling of the situation by the police officials.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Sir, I wish to raise an issue which has already been raised on the floor of the Maharashtra Assembly, where it has been pointed out that there is a group of persons who have been indulging in a number of malpractices in the Security Printing Press at Nasik, under the leadership of a person called Vijay Ranade. This gang has been stealing some of the important documents and letterheads in the name of the President of India and they have utilised them for securing import licences to the tune of lakhs of rupees. Vijay Ranade is supposed to be staying at Arunoday Lodge at Nasik and he was parading in the fake names of Rajadhyakasha, Capt. Desai and Maj. Marathe. There is another culprit by name Shri R. J. Munshi. All the details have been given on the floor of the Maharashtra Assembly. It was indicated there that since this comes within the jurisdiction of the Central Government, perhaps more information will be available from the Centre. You will agree that this is a very serious matter and I demand a categorical statement from the minister concerned, so that these malpractices being indulged in the name of the President of India at the Security Press at Nasik can be ended.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai) : I would like to make a statement on certain matters which are likely to affect the free and fair elections in Gujarat. As the House knows on the 22nd of this month, we have been invited by the Prime Minister of India to a meeting in connection with the electoral reforms. But in the meantime, there is a spurt in the enthusiasm of the central Government for expediting some of the projects in Gujarat. This has been recognised to be one of the evil practices and the courts have pronounced their opinions on it.

The second point relates to the conduct of a civil servant. Recently we had raised this matter as to how a civil servant, Mr. Sarin, who acts as the Adviser to

[Shri Shyamnandan Mishra]

the Government of Gujarat was involved in a television interview. That point was not cleared to the satisfaction of the hon. members of this House. In the meantime, we reliably learn that when Mr. Sarin was recently here, he participated in one of the meetings of the ruling party members in connection with the elections. He has been dabbling in active politics.

AN HON. MEMBER : May be he has joined the ruling party.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : If he has joined the ruling party, that would be to the great relief of all of us. I want that Government should clarify this also.

There is another matter to which I would like to draw the attention of the House and ask the Government to make a statement. The all India Radio had been making broadcasts about the famine and drought conditions in Gujarat. But soon after the termination of the fast by Mr. Morarji Desai and announcement of the elections, the All India Radio had discontinued its broadcasts on the drought conditions in Gujarat. Are they proposing to devote all the time to partisan broadcasts, leaving the drought-affected people to fend for themselves ?

Lastly, I would draw the attention of the Government to the lack of drinking water in many parts of Bihar, to which Mr. Shastri also has referred. Government must take some active steps with regard to this. I would particularly draw attention to the helpless people of my constituency Beghusarai in this context.

SHRI B. V. NAIK (Kanara) : The work in regard to a very major hydro-electric project in this country which is situated in the district of South Kanara in Karanataka has been held up, we are given to understand, due to paucity of funds. The project was cleared as early as 29th July 1973. Subsequently we have been hearing appeals from the Governor of Karnataka, Mr. Sukhadia, to the centre for funds. This is the *Hindu* dated 26th December, 1974. There are other items in Hindu of 22nd February and 10th March 1975 about it. The crux of the problem is that the State Government has carried out certain works in respect of the Kali hydel project. It is going to generate the cheapest electricity in the whole of Asia, costing as little as 3.5 paise per unit. The correct point has been raised by Shri Brij Raj Singh that the greater the delay, the higher will be the cost per unit, and there will be an escalation of the cost. It is, therefore, all the more necessary to see to it that the project is completed as soon as possible. The total requirements of the project are about Rs. 200 crores. I do not know whether in the central Ministry of Energy there are any apprehensions either regarding any section of the project or the utilisation of the funds. But one of the local problems that is very much evident is that an entire township, a former Taluk or Suba with three to five thousand souls is going to be completely under water under the dam site. Resettlement of these prople has not been done.

There are certain local and State problems, but the centre cannot drag its feet or sleep over the matter. If necessary, time should be found for a discussion in detail of the hydel projects, and specifically the Kali project which will generate as much as 1250 m.w. of power if it is fully commissioned. I request that the Central Government in the Ministry of Energy should depute as soon as possible a Central study team to make an on-the-spot survey as well as a study of the situation there.

SHRI K. RAGHURAMAIAH : Regarding the point raised by Shri Sezhiyan I do realise that there has been some slipping up in spite of instructions. Since then my Department has been informed that the Director of Printing has issued a fresh circular. Let us hope that no such thing will occur in future.

Regarding the other matters, as is the convention in the House, I shall most faithfully convey to the Ministers concerned the laudable sentiments of the House.

PROF. MADHU DANDAVATE : You have already directed that the Minister should make a statement on the issue of President's papers being stolen from the Nasik Security Press.

MR. SPEAKER : This is a time which so many Members use. You come in the morning with this and then you raise, and you expect the Minister to be ready to answer.

PROF. MADHU DANDAVATE : At a later stage let him make a statemen

SHRI S. M. BANERJEE : Seven or eight days before you gave a direction to the Minister of Energy to make a statement about the power failure or scarcity in Kanpur. A large number of employees are affected.

MR. SPEAKER : About that the Minister agreed. He must come forward with a statement.

SHRI K. RAGHURAMAIAH : The usual practice is that I convey to the Minister concerned what he has actually said. The Minister has to take action.

SHRI S. M. BANERJEE : I am not making a statement today. On that day you were very angry and so was I. Ultimately, when I cooled down, you were kind enough to direct the Minister to make a statement.

There is a serious situation in Kanpur, in the whole of U. P., affecting two lakhs of workers, and the Minister goes on merrily, he has no time to make a statement He may have no respect for me, but he should have respect for you I request you to see that he makes a statement.

MR SPEAKER : Before this observation came from you, I have already directed him.

SHRI S M BANERJEE : You suspend the Minister for a day

MR. SPEAKER : In view of this particular practice that after your statement about the business for the coming week, Members raise their questions, you must have a new portfolio of only a Minister of Statements. Or it should be directly under the Speaker.

PROF. MADHU DANDAVATE : I did not press my adjournment motion when you categorically directed the Minister so make a statement. Our Minister of Parliamentary Affairs should take note of this direction.

12.53 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE

CENTRAL ADVISORY BOARD OF EDUCATION

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV) : I beg to move :

> "That in pursuance of paragraph 5(3) (a) of the late Department of Education, Health and Lands Resolution No. F/122-3/35-E, dated the 8th August, 1935, as amended from time to time, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, four members from among themselves to serve as members of the Central Advisory Board of Education, subject to the other provisions of the said Resolution."

MR. SPEAKER : The question is : "That in pursuance of paragraph 5(5)(a) of the late Department of Education, Health and Lands Resolution No. F/122-3/35-E, dated the 8th August, 1935, as amended from time to time, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, four members from among themselves to serve as members of the Central Advisory Board of Education, subject to the other provisions of the said Resolution."

The motion was adopted

12-54 Hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1975-76—*contd.*

MINISTRY OF DEFENCE—*contd.*

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय मैं भारत की उत्तरी सीमा की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा था । उस संबंध में मैं ने चर्चा किया कि उत्तर मे चीन अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। सामरिक शक्ति अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर वह बढाता तो हमें चिन्ता नहीं होती लेकिन वह तो शक्ति बढ़ रही है हमारी बिलकुल उत्तरी सीमा के निकट । सदन को मालूम है कि नैपाल एक बहुत छोटा सा देश है। उस के उत्तर की तरफ तिब्बत की तरफ से काठमांडू तक चीन ने जो सड़क बना ली है उस के अलावा भी अभी हाल में जो समाचार मिले हैं उस के अनुसार एक दो चार नहीं बल्कि पन्द्रह बीस सड़कें तिब्बत